

8 व 9 अप्रैल को गुजरात में ए.आई.सी.सी. की बैठक है

अहम सवाल है कि बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का भविष्य क्या होगा? क्योंकि, जब भी गुजरात में ए.आई.सी.सी. बैठक हुई है, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष को विवादों के कारण हटना पड़ा है

-रेणु मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अप्रैल। आठ और नौ अप्रैल को अहमदाबाद में ए.आई.सी.सी. अधिवेशन होने जा रहा है, पर कांग्रेस पर नजदीक से नजर रखने वाले लोगों तथा विश्लेषकों के मन में एक सवाल खलबली पैदा कर रहा है कि इस ए.आई.सी.सी. अधिवेशन के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भविष्य क्या होगा। यह गुजरात में आयोजित होने वाला छठा ए.आई.सी.सी. अधिवेशन होगा। उल्लेखनीय है कि गुजरात में हुए विभिन्न ए.आई.सी.सी. अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाले 5 कांग्रेस अध्यक्षों के प्रति समय उदार नहीं रहा है। या तो वे पार्टी छोड़ गये और उन्होंने अपनी स्वयं की नयी पार्टी बना ली या फिर उन्होंने स्वयं को कांग्रेस से अलग कर लिया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसम्बर, 1885 को हुई थी।

इसका पहला अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में 23-26 दिसम्बर 1902 को सुरेन्द्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। बाद में, पार्टी के अंदर पैदा हुये मतभेदों तथा उनके

■ गुजरात में ए.आई.सी.सी. की बैठक 1902 में हुई थी तथा बैठक के बाद अध्यक्ष सुरेन्द्र नाथ बनर्जी को हटना पड़ा था, उनके खिलाफ आंतरिक विद्रोह के कारण।

■ दूसरी बार, 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में गुजरात में बैठक आयोजित हुई थी और उन्हें भी आंतरिक मतभेदों के कारण बैठक के बाद पार्टी छोड़नी पड़ी थी।

■ तीसरी बार, 1921 में ए.आई.सी.सी. की बैठक गुजरात में हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में हुई थी, उनका भी वो ही हथ्र हुआ था, बैठक में, जो पहले दो अध्यक्षों का हुआ था।

■ चौथी बार, ए.आई.सी.सी. की बैठक 1938 में हुई, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अध्यक्षता में। बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार को पार्टी के आंतरिक चुनाव में हराया था तथा यह मतभेदों का बड़ा कारण बना और सुभाष बाबू को अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

■ पाँचवीं बार गुजरात में ए.आई.सी.सी. की बैठक नीलम संजीवा रेड्डी की अध्यक्षता में हुई तथा बैठक के बाद कांग्रेस में विभाजन हुआ और इस विभाजन के बाद नीलम संजीवा रेड्डी की संयुक्त कांग्रेस की अध्यक्षता तो खत्म होनी ही थी।

■ अब छठी बार, गुजरात में ए.आई.सी.सी. की बैठक आयोजित की गई है। अतः स्वाभाविक सवाल है, इस बैठक के बाद, क्या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी की अध्यक्षता सुरक्षित और बरकरार रहेगी तथा ऐतिहासिक परम्परा टूटेगी।

खिलाफ पार्टी में हुई बगावत के कारण, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी तथा अपना नया संगठन बना लिया था।

इसके बाद, 26-27 दिसम्बर,

1907 को पार्टी का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष रास बिहारी बोस ने की थी। वे भी मतभेदों के कारण पार्टी छोड़ गये थे।

तीसरी बार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 27-28 दिसम्बर, 1921 को फिर से अहमदाबाद, गुजरात (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेलंगाना के मु.मंत्री को भारी पड़ा, लोकप्रिय फिल्म एक्ट्रेस पर झूठा आरोप लगाना

रैवन्त रेड्डी ने दिया मिर्जा पर आरोप लगाया कि उन्होंने ए.आई. जैनरेटेड फोटोग्राफ लगायीं, आंदोलन का "हौवा" दिखाने के लिए

-लक्ष्मण वैकट कुची-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अप्रैल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री एक "चार्म" हैं जल्दी ही लोगों को लुभा लेते हैं और मीडिया तथा अन्य कथानकों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में माहिर हैं पर सैलिब्रिटीज पर कंचा गाचीबोवली जंगल पर फक न्यूज व एआई से बने वीडियो फैलाने का आरोप लगाकर उन्होंने खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर ली है।

बेहद साहसी सैलिब्रिटीज में से एक दिया मिर्जा, जो हैदराबाद से ही हैं, ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और रैवन्त रेड्डी की इस बात के लिए कड़ी निंदा की क्योंकि इन्होंने उन पर झूठे एआई वीडियो व फोटो फैलाने का झूठा आरोप लगाया। दिया मिर्जा ने 400 एकड़ वन भूमि, जिसे सरकार नीलाम करना चाहती है, से पेड़ काटने के खिलाफ

■ दिया मिर्जा ने कड़ा विरोध किया कि मु.मंत्री को तथ्य जान लेने चाहिए, कोई आरोप लगाने से पहले।

■ अन्य फिल्म हस्तियों, जैसे, जॉन अब्राहम, रवीना टण्डन ने भी दिया मिर्जा का पूर्ण समर्थन किया।

आंदोलन कर रहे छात्रों के पक्ष में कुछ वीडियो व तस्वीरें पोस्ट की हैं। रेड्डी का आरोप है कि ये वीडियो व तस्वीरें एआई से तैयार हैं। फिल्म स्टार दिया मिर्जा, जो संवेदनशील किरदारों और शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं, ने अपने एक्स एकाउंट पर रैवन्त रेड्डी के आरोपों को "पूरी तरह से झूठ" करार दिया और कहा कि मैंने एआई जनरेटेड फोटो व वीडियो का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कल एक टवीट किया जिसमें कंचा गाचीबोवली के बारे में कुछ दावे किए उनमें एक था कि 400 एकड़ जमीन, जिसे सरकार बेचना

चाहती है, की जैवविविधता को बचाने के विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के पक्ष में मैंने फेक एआई जनरेटेड फोटो व वीडियो पोस्ट किए हैं। यह एक गलत बयान है मैंने ऐसी एक भी तस्वीर या वीडियो पोस्ट नहीं किया है जो एआई से तैयार किया गया हो।

अभिनेत्री ने मीडिया और राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा, "मीडिया और तेलंगाना सरकार को ऐसे दावे करने से पहले अपने तथ्यों की जांच करनी चाहिए।"

सोशल मीडिया पर कंचा गाचीबोवली में पेड़ों को गिराने से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुनर्गठन व परिसीमन के बाद पंचायत चुनाव कार्यक्रम तय होगा

जयपुर, 7 अप्रैल। प्रदेश की 6759 पंचायतों के चुनाव स्थगित कर, निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक बना दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका में राज्य सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया है। वहीं, सोमवार को मामले का नंबर नहीं आने के कारण मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच में मामले की चल रही सुनवाई दो सप्ताह के लिए टल गई है।

राज्य सरकार की ओर से पेश शपथ

■ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अतिरिक्त शपथ पत्र पेश कर यह जानकारी दी।

पत्र में कहा गया कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के पुनर्गठन व परिसीमन के लिए मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया मई-जून महीने तक चलनी और उसके बाद ही पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा। दरअसल, गिरांज सिंह व अन्य की पीआईएल में पिछली सुनवाई पर खंडपीठ ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग से पूछा था कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्टालिन तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव, मोदी बनाम स्टालिन संघर्ष बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं

ममता बनर्जी की भांति स्टालिन का भी तमिलनाडु के मीडिया पर पूरा कंट्रोल है तथा वो स्थानीय मीडिया का एजेण्डा निर्धारित कर रहे हैं

-लक्ष्मण वैकट कुची-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अप्रैल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टालिन ने खुद को सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुकाबले में खड़ा कर दिया है। वे खुद को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं, मानो सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं, जैसे ए.बंगाल में ममता बनर्जी दे रही हैं, जहाँ अगले वर्ष चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने तमिलनाडु के पर्वन ब्रिज के उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लिया। इस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। इसके बाद अन्नामलाई के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने हमानां शुरु कर दिया और आरोप लगाने लगे कि स्टालिन ने उद्घाटन समारोह में भाग न लेकर प्रधानमंत्री का अपमान किया है। यही नहीं, जब प्रधानमंत्री राज्य में आए तो स्टालिन ने उनका स्वागत तक नहीं किया। उनकी बजाय उपमुख्यमंत्री पी. त्यागराजन ने प्रधानमंत्री का स्वागत

■ मोदी बनाम स्टालिन का वातावरण बनाने के लिए उन्होंने स्थानीय मुद्दे, डीलिटिमेशन, नई शिक्षा नीति, नीट परीक्षा का विरोध आदि मुद्दे उठाए और अब प्र.मंत्री मोदी की तमिलनाडु यात्रा में भी वे न.प्र.मंत्री का स्वागत करने हवाई अड्डे गये और न ही प्र.मंत्री के समारोह में शरीक हुए।

■ वे तमिलनाडु के पुराने मुद्दों को भी, जैसे काचातीवू टापू के विवाद को, ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे कि यह मोदी के सत्ता में आने से पैदा हुआ है।

किया। मुख्यमंत्री स्टालिन जो भी करते हैं या कर रहे हैं, उसमें पूरी सोची समझी रणनीति होती है। वे पूरे विषय को खुद के और प्रधानमंत्री के मुकाबले में बदल देते हैं। स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने काचातीवू द्वीप वापस लेने की तमिलनाडु की मांग की उपेक्षा की है। स्टालिन ने शब्दों से ऐसा लगता है, जैसे यह समस्या मोदी सरकार की देन है। स्टालिन ने कहा कि केन्द्र सरकार

बाजारों की इस उथल-पुथल के बीच, 29 देशों वाली यूरोपियन यूनियन (ई.यू.) ने टैप के पिछले सप्ताह के शुल्कों के जवाब में अपने खुद के शुल्कों की घोषणा की। यूरोपीय संघ ने अमेरिका से आयात पर 28 बिलियन डॉलर के शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा। ई.यू. के व्यापार आयुक्त ने कहा कि ये शुल्क 9 अप्रैल से प्रभावी होंगे।

चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिसे टैप "नम्बर वन" दुश्मन मानते हैं, ने अमेरिका से आयात पर 34 प्रतिशत से अधिक शुल्क लगाने की घोषणा की है। अब चीन अमेरिका से आयात पर अपने शुल्कों को और बढ़ाने और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है।

अमेरिका के रैसप्रोकल टैरिफ और अन्य टैक्स, जिसमें 10 प्रतिशत का बेसिक टैक्स भी शामिल है, के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वक्फ विधेयक का पारित होना। राज्य को शिक्षा-फंड जारी करने से केन्द्र के इनकार को भी द्रमुक तथा उसका प्रचार-तंत्र, तमिलनाडु के प्रति केन्द्र के सौतेले व्यवहार के एक और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि द्रमुक का प्रचार तंत्र, कम से कम तमिलनाडु में तो, भाजपा के प्रचार तंत्र से कम नहीं पड़ता, बल्कि उसे पछाड़ने की कुव्वत रखता है। टीक परिचम बंगाल की तरह, जहाँ स्थानीय मीडिया पर ममता बनर्जी तथा उनकी पार्टी की पूरी पकड़ है, तमिलनाडु में द्रमुक के अपने स्वयं के बहुत ताकतवर मीडिया ब्रांड हैं तथा द्रमुक की मीडिया-प्रबंधन रणनीति पूरी तरह अभेद्य है। इस क्षेत्रीय दल के पास इस मामले में जो ताकत है, उसका उसके राष्ट्रीय पार्टनर, कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर अभाव साफ दिखाई देता है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एकल पट्टा प्रकरण में अशोक पाठक को पक्षकार बनाने पर बहस जारी

जयपुर, 7 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को पूर्व मंत्री शांति धारीवाल से जुड़े चर्चित एकल पट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता रहे अशोक पाठक को पक्षकार बनाए जाने के मुद्दे पर बहस जारी रही। अदालत मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगी।

मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ के समक्ष पूर्व मंत्री

■ पूर्व मंत्री धारीवाल के अधिवक्ता ने पाठक को पक्षकार बनाने पर आपत्ति की। धारीवाल के अधिवक्ता वीआर बाजवा ने पाठक को पक्षकार बनाए जाने पर आपत्ति जताई। बाजवा ने कहा कि अशोक पाठक मामले में न तो शिकायतकर्ता हैं और न ही उनके कोई हित प्रभावित हुए हैं। ऐसे में उनका इस केस से कोई संबंध नहीं है। जवाब में पाठक के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ हाई कोर्ट ने लापता नाबालिगों के चार मामलों में डीजीपी यू.आर. साहू को बुलाकर तीखी टिप्पणी की।

में कारवाई शुरू हो जाती है। कई मामलों में तो लापता की बरामदगी भी हो जाती है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित ने यह टिप्पणी नाबालिग लापताओं के चार मामलों में सुनवाई के दौरान, डीजीपी यूआर साहू अदालत में पेश हुए। उनके साथ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूरोपियन यूनियन, चीन, कैनडा, मैक्सिको ने अमेरिका से इन देशों को निर्यात होने वाले सामान पर भारी टैरिफ वृद्धि जड़ी

-अंजन रांय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अप्रैल। टैप की टैरिफ तथा ट्रेड की गलाघाँव वाणिज्यिक व व्यापारिक नीतियों के कारण एक ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर छिड़ गया है, जिसमें सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं नए अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को सबक सिखाने के लिए सख्त कदम उठा रही हैं। टैरिफ (शुल्क) एक दोधारी तलवार की तरह है। यदि आप दूसरों पर शुल्क लगाते हैं तो वो भी आपके खिलाफ समान या और अधिक कठोर कदम उठा सकते हैं। इसका परिणाम, बढ़ती महंगाई, घटता व्यापार, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी, लोगों की आय में गिरावट और भारी बेरोजगारी हो सकता है। ट्रंप द्वारा रैसप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद सोमवार को जब स्टॉक मार्केट खुले तो विश्व भर के स्टॉक बाजारों में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला।

स्टॉक मार्केट "बेयर मार्केट" की स्थिति में है, जिसका अर्थ है कि इस समय इन्वैस्टर अपना इन्वैस्टमेंट बेचकर नकदी रखना पसंद करेंगे, बजाय स्टॉक्स में पैसा लगाने के। जापान का स्टॉक मार्केट, जो दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में एक है, टैरिफ वॉर के कारण सोमवार को 8 प्रतिशत गिर गया। भारत के स्टॉक मार्केट में 2227 पॉइंट की गिरावट आई, जिसने 14 लाख करोड़ रूपए की शेयर वैल्यू को मिटा दिया। चीन का शेयर बाजार भी गिरा। यूरोपीय बाजार को 10 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1.7 ट्रिलियन यूरो का नुकसान झेलना पड़ा।

■ यूरोपीय देशों ने 28 अरब डॉलर का आयात शुल्क लगाया।

■ चीन ने 34 प्रतिशत का टैरिफ लगाया अमेरिकी सामान पर।

■ ये देश, टैरिफ युद्ध में इसलिये उतरे कि अमेरिका के टैरिफ धमाकों से इन सभी देशों के स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की कीमतों में गिरावट आई

■ जापान के स्टॉक एक्सचेंज में 8 प्रतिशत की गिरावट आई, चीन के स्टॉक मार्केट में दस प्रतिशत टूट हुई। जैसा कि विदित ही है अमेरिका ने चीन के माल पर 54 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है।

■ जे.पी. मॉर्गन बैंक (अमेरिका) के अध्यक्ष जैमी डीमॉन ने शेयर होल्डर्स को संबोधित करते हुए कहा, अमेरिका की विशेष पोजिशन थी, विश्व में, अपनी इकोनॉमी की ताकत, सेना के "पावर" और अपनी नैतिक मान्यताओं के कारण, जिसका मुख्य हिस्सा थी इकोनॉमी व राजनीति में स्वतंत्रता, पर, अब यह मान्यता खत्म हो रही है।